संख्या-60/2019/955/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 08 मार्च 2019

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2869-70/स0क0/विकास/सिद्धार्थनगर(122)/2018-19, दिनांक-01.03.2019, पत्रांक-2912-13/स0क0/विकास/सिद्धार्थनगर(126)/2018-19, दिनांक-01.03.2019 एवं पत्रांक-2842-43/स0क0/विकास/सिद्धार्थनगर(119)/2018-19,दिनांक-26.02.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पेयजल के लिये जल शुद्धिकरण निर्माण कार्य के लिये आंकलित धनराशि रू0-54.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0-50.00 लाख, आवास निर्माण कार्य हेतु आंकलित धनराशि रू0-49.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0-49.99 लाख एवं 04-सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु आंकलित धनराशि रू0-192.76 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0-101.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

जनपद-सिद्धार्थनगर विकासखण्ड-भनवापुर (धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	आंकलित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	सेखुई गोबर्धन।	पेयजल के लिये जल शुद्धिकरण निर्माण कार्य।	54.72	50.00
2	सेखुई गोबर्धन।	आवास निर्माण	49.99	49.99
3	सेखुई गोबर्धन	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	48.19	25.45
4	धनोहरा	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	48.19	25.45
5	अन्दुवाशनिचर	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	48.19	25.45
6	मन्नीजोत।	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	48.19	25.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ) से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1001-पेय जल व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य, 1002-आवास निर्माण-24-वृहत निर्माण एवं 1004-सामुदायिक केन्द्र का निर्माण-24वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-60/2019/955(1)/26-3-2019 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी सिद्धार्थनगर।

3.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

6.प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ)।

7.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

8.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

10.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।